

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2355

दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 / 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में कमी

2355. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा में कोई कमी आई है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद की हिंसा को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जी हाँ, श्रीमान। वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने के लिए 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' के केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सुदृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों तथा हिंसा में सतत कमी आयी है।

LWE सम्बंधित हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 के उच्च स्तरों की तुलना में वर्ष 2023 में 73% तक की कमी हुई है। इसी अवधि के दौरान, परिणामी मौतों (आम नागरिक+सुरक्षा बलों) में भी 86% तक की कमी हुई है। पिछले वर्ष 2023 की तुलना में, इस वर्ष 2024 में जनवरी से 15 नवम्बर तक की अवधि के दौरान भी वामपंथी उग्रवादी हिंसक घटनाओं में 25% तक की कमी हुई है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी लगातार गिरावट आई है। स्थिति में लगातार हो रहे सुधार के मद्देनजर, पिछले छः वर्षों में LWE प्रभावित जिलों की तीन समीक्षाएं की गई हैं, जिनमें LWE प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल, 2018 में 126 से घटकर 90 जिले हो गई। प्रभावित जिले जुलाई, 2021 में और कम होकर 70 तथा बाद में अप्रैल, 2024 में 38 रह गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2355, दिनांक 10.12.2024

(ग): वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को अनुमोदित किया गया था। इसमें एक बहुआयामी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। जहां सुरक्षा की दृष्टि से, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनों, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु प्रशिक्षण एवं निधियों, उपकरण एवं हथियारों, आसूचना के आदान-प्रदान, फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि का प्रावधान करके LWE प्रभावित राज्यों की सहायता करती है, वहीं विकास की दृष्टि से प्रमुख योजनाओं के अलावा, भारत सरकार ने सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, कौशल और वित्तीय समावेश पर विशेष जोर देते हुए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहलें की हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के मध्य अर्थात पिछले 05 वर्षों के दौरान, विशेष अवसंरचना योजना (SIS), सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) और विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजनाओं के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता संवर्धन के लिए 4350.78 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन (ACALWEM) योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में हेलीकॉप्टरों और महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए पिछले 05 वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान, केंद्रीय एजेंसियों को 560.22 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विकास की दृष्टि से कई पहलें की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए अब तक, 14469 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।
- दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, 6567 टावर स्थापित किए गए हैं।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्थानीय लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए, 5731 नए डाकघर खोले गए हैं। साथ ही, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में 1007 बैंक शाखाएं तथा 937 एटीएम खोले गए हैं।
- कौशल विकास के लिए, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 46 ITI और 49 कौशल विकास केंद्र (SDC) खोले गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2355, दिनांक 10.12.2024

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के जनजातीय समूहों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (EMRS) स्थापित किए गए हैं।

सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CRPF, BSF, SSB और ITBP) स्थानीय लोगों के कल्याण और युवाओं को माओवादियों के प्रभाव से दूर रखने के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय करते हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के जनजातीय युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS) के माध्यम से ट्राईबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (TYEP) आयोजित किए जा रहे हैं।
